in Gujarat, Maharashtra, Goa and Lakshadweep.

(d) Question does not arise.

### भ्रष्टाचार का उन्मूलन

2527. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (श्री आर० जनार्दन):** (क) से (ग) सरकार स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया अभियान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में, बनाई गई नीतियों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि इन्हें बदलते परिवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावोत्पादक, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया जा सके। सचिव और विभागाध्यक्ष अपने-अपने मंत्रालय/विभाग में भ्रष्टाचार की रोकथाम (करने) के लिए जिम्मेवार होते हैं। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और मंत्रालयों/विभागों में आंतरिक सतर्कता-तंत्र ऐसे अभिकरण (एजेंसियां) है जो इस कार्य में संलग्न है।

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का प्रशासनिक सतर्कता-प्रभाग, जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता देने के अलावा मंत्रालयों/विभागों द्वारा सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोधी क्षेत्र में किए गए उपायों संबंधी प्रयासों को समन्वित करता है। कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार की जाती है, जो निवारण, निगरानी और सुगरगसानी तथा दंडात्मक निवारक कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम में सहायता करती है। ये योजनाएं संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह कार्य आरम्भिक तौर पर, वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था और इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा है।

सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की दृष्टि से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूलतः 1947 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण-अधिनियम, 1988 को पुनः अधिनियमित करके पहले की अपेक्षा और ज्यादा सशक्त बना दिया गया है, फलतः यह अब अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हो गया है। वर्ष, 1988 के नये अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:—

(क) "लोक सेवक" शब्द की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करके इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार अथवा बैंकिंग आदि से संबंद्ध पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का शामिल किया जाना;

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु विशेष-न्यायालय स्थापित किए जाने संबंधी उपबंध का अन्तःस्थापित किया जाना।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165क के तहत अपराधों का अन्तःस्थापित किया जाना; और

(घ) "आय के ज्ञात स्रोत" जिसका अभिप्राय आय के केवल विधिसम्मत स्रोत से है शब्द की परिभाषा का अन्तःस्थापित किया जाना।

इसके अतिरिक्त लोक-सेवकों की सेवा-शर्तों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न आचरण-नियमों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित, निवारक उपाय, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक का भी कार्य करते हैं। उच्च लोक-कृत्यकालरियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए लोकपाल संस्था का स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है।

### News-Item Captioned "Enhanced Dues a Mirage for Pensioners"

2528. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan times, dated 21st April, 1998 captioned "Enhanced dues a mirage for pensioners";

(b) if so, the details thereof; and

(c) what concrete steps Government have taken, so far, to ensure that no Central Government pensioner is

deprived of his dues and relevant information/details made available with Banks, particularly those who retired in 1990 and onwards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The news-item dated 21st April, 1998 related to revision of pension of Pre-1986 retirees. While implementing decisions on the recommendation of the Vth Central Pay Commission, the Government has already issued orders for the revision of pension/family pesnion of pre-1986 retirees on the basis of fixation of notional pay in the pay scales introduced w.e.f. 1.1.1986. As per the procedure laid down in these instructions, pre-1986 pensioners/family pensioners are required to apply for the revision of their pension to the head of Department where the pensioner/deceased Government servant served last before his retirement/death. A fixed time schedule has also been laid down for dealing with such cases of revision of pension by various authorities. It has been impressed upon all the Ministries/ Departments etc. to deal with these cases on priority basis. The Government has also issued orders that pending revison of their pension/family pension of pre-1986 retirees, their existing pension may be consolidated as on 1.1.1996 by adding together basic pension, DA admissible at AICPI 1510, IR(I) & (II) and 40% Fitment Weightage so as to provide immediate relief based on the table attached to the orders dated 27.10.1997. orders for release of first instalment of arrears on this account amounting to Rs. 5000/- plus 50% of the remaining amount were issued on 27.10.1997. Orders for the relase of second and final instalment have also been issued on 27.5.1998. With a view to mitigate hardships to pensioners/family pensioners on account of non-availablility of relevant records in cases where the pensioner had retired prior to 1.1.1973, it has been provided in the orders for the Head of office to fix their pay at the minimum of the scale of pay introduced w.e.f. 1.1.1973 for the post held by them before retirement. Orders dated 27.10.1997 referred to above also provide for revision of pension/family pension of those who retired between 1.1.1986 to 31.12.1995.

**Officers on Deputation in the Central Government**

2529. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are not granting extension to officers on deputation on completion of their tenure in the Central Government;

(b) whether Government are aware that some officers have been continuing on Central deputation much beyond the prescribed period;

(c) whether Government intend to revert all such officers immediately as these officers have developed vested interests; and

(d) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) According to the provisions contained in the Central Staffing Scheme every officer shall revert at the end of his tenure on the exact date of completion of his tenure. As per the guidelines laid down by the Government, any proposal for extension in the tenure of an officer beyond the normal tenure is considered only where there is strong justification.

(b) to (d) There are presently some officers who are on tenure extended in